



सरकार और RBI के बीच मतभेद

प्रलिस के लयि:

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI), RBI गवर्नर, रेपो रेट, रविर्स रेपो रेट, CRR

मेन्स के लयि:

RBI की कार्यप्रणाली, RBI और केंद्र सरकार के बीच मतभेद के मुख्य कारण

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो गया, जसिमे उनके दूसरे कार्यकाल के अंत में सरकार के साथ कुछ मतभेद की स्थतिबिनी रही।

- RBI और सरकार के बीच असहमति आर्थिक मंदी और GDP वृद्धि को बढ़ावा देने के लयि कदम उठाने की सरकार की अपील के बावजूदनीतगित दरों में कटौती से बचने के केंद्रीय बैंक के फैसले से उत्पन्न हुई।

नोट: मंत्रमिंडल की नयिकृतसमिति ने वर्तमान में वत्ति मंत्रालय में राजस्व सचवि के रूप में कार्यरत 56 वर्षीय संजय मलहोत्रा को भारतीय रज़िर्व बैंक के 26 वें गवर्नर के रूप में नयिकृत करने की मंजूरी दे दी है।

RBI और केंद्र सरकार के बीच प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- त्वरति सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) के मानदंडों को आसान बनाना: सरकार ने RBI से MSME के लयि ऋण को बढ़ावा देने के लयि PCA के तहत वदियुत कंपनयिों को छूट देने और ऋण नयिमों को आसान बनाने का आग्रह कयिा, लेकनि RBI ने ऐसे उपायों का वरिध कयिा है।
 - उन्होंने तर्क दयिा कि PCA के तहत मानदंडों में ढील देने से गैर-नषिपादति परसिंपत्ता (NPA) संकट से नपिटने के प्रयासों को नुकसान पहुँच सकता है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लयि एक बड़ी चुनौती बन गया है।
- RBI अधनियम, 1934 की धारा 7: सरकार, RBI अधनियम की धारा 7 के तहत, सार्वजनिक हति में RBI को नरिदेश दे सकती है, लेकनि इसके उचित उपयोग न होने से RBI की स्वायत्तता को कम करने के बारे में चतिा जताई गई है।
 - जबकि सरकार बयाज दरों को कम करने जैसे उपायों के माध्यम से अल्पकालिक विकास को प्राथमकता देती है, RBI मुद्रास्फीति नयितरण, मूल्य स्थरिता और दीर्घकालिक वत्तितीय स्थरिता पर ध्यान केंद्रति करता है, जसिके कारण कभी-कभी नीतगित मतभेद पैदा हो जाता है।
- RBI अधशिष: RBI बॉण्ड से आय अर्जति करता है और अधशिष का एक हसिसा आकस्मिक नधि और परसिंपत्ता रज़िर्व जैसे बफर के लयि रखता है।
 - यह देखा गया है कि सरकार प्रायः अतरिकृत रज़िर्व का तर्क देते हुए अधिक लाभांश की मांग करती है, जबकि RBI मुद्रास्फीति के ज़ोखमि और व्यापक आर्थिक स्थरिता के लयि खतरों की चेतावनी देता है।
 - अधशिष मुद्रा मूल्य में उतार-चढ़ाव और स्वरण के मूल्यहरास के खिलाफ सुरक्षा के रूप में भी कार्य करता है।
- नयामक प्राधकिरण और संस्थागत कषेत्तर : वत्तितीय स्थरिता और विकास परषिद (FSDC) जैसे नकियों के नरिमाण से RBI के भीतर वत्तितीय वनियमन में इसकी घटती भूमिका के बारे में चतिा पैदा हो गई है।
 - इसके अलावा, RBI के प्रमुख अधिकारयिों की नयिकृता में सरकार के प्रभाव के मुद्दे पर भी मतभेद है, केंद्रीय बैंक ने चतिा व्यक्त की है कि इस तरह का हसतकषेप उसकी स्वतंत्रता को चुनौती देते हैं।
- वदिशी मुद्रा पर मुद्दा: RBI ने राजकोषीय घाटे या ऋण माफी के लयि वदिशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने के सरकार की मांग का वरिध कयिा है,

क्योंकि उसे डर है कि इससे वित्तीय स्थिरता प्रभावित होगी और रुपया कमजोर होगा, जिससे रज़िर्व प्रबंधन पर असहमता पैदा होगी।

- **RBI वित्तीय स्थिरता और रुपए की मज़बूती** के लिये जोखिम का हवाला देकर इस मांग का वरिध करता है। इसके अतिरिक्त **वित्तीय समावेशन** और **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को ऋण देने के लिये सरकार का ज़ोर प्रायः RBI के समग्र वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के फोकस के साथ टकराव करता है।

RBI गवर्नर और सरकार के बीच पहले क्या मतभेद हुए थे?

- **RBI गवर्नर वाई.वी. रेड्डी (2003-2008):** ब्याज दरों में कटौती और **वित्तीय बाज़ार विकास** को लेकर तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ उनके मतभेद थे। उन्होंने किसानों के ऋण माफ करने तथा बिना गारंटी के विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने के प्रस्तावों का वरिध किया।
- **डी. सुब्बाराव (2008-2013):** उनके कार्यकाल में **मुद्रास्फीति वरिधी नीतियों को लेकर मतभेद** देखा गया, जिसमें सरकारी अधिकारी उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद कम ब्याज दरों पर ज़ोर देते रहे।
- **रघुराम राजन (2013-2016):** उन्हें उस समय भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब सरकार ने RBI से परामर्श किये बिना **भारतीय प्रतभिता और वनियम बोर्ड (SEBI)** के माध्यम से मुद्रा बाज़ार को वनियमिती करने का प्रयास किया। उन्होंने **वमिद्रीकरण की संभावति लागतों और लाभों** के बारे में चर्चा जताई, जसिे सरकार ने उनकी सहमति के बिना ही लागू कर दिया।
- **उरजति पटेल (2016-2018):** उनके कार्यकाल में **अधशेष हस्तांतरण और ऋण मानदंडों** पर असहमति देखी गई। सरकार ने RBI की नीतियों के बारे में चर्चा करने के लिये **RBI अधनियम की धारा 7** का प्रयोग किया।
 - उन्होंने बढ़ते तनाव के बीच वशेष रूप से RBI के पूंजी भंडार तक पहुँच बनाने के सरकार के प्रयासों के संबंध में इस्तीफा दिया।

आगे की राह

- **RBI-सरकार संबंधों को मज़बूत करना:** स्वतंत्र नरीक्षण तंत्र योग्यता आधारति नयुक्तियों को सुनश्चिति कर सकता है और RBI को अनुचति राजनीतिक प्रभाव से बचा सकता है।
 - भूमिकाओं का स्पष्ट चर्चण आवश्यक है, जसिमें सरकार राजकोषीय नीतियों और विकास पर ध्यान केंद्रति करेगी, जबकि **RBI मौद्रकि नीति** और वित्तीय स्थिरता को प्राथमकिता देगा।
- **RBI की स्वायत्तता को मज़बूत करना:** सरकार को **RBI** के साथ अल्पकालकि उपायों को लागू करने के लिये आम सहमति बनानी चाहति, जो दीर्घकालकि वित्तीय स्थिरता से समझौता करते हैं।
 - **स्पष्ट कानूनी और संस्थागत ढाँचे** से RBI की स्वायत्तता को सुदृढ़ किया जा सकता है, तथा यह सुनश्चिति किया जा सकता है कि वह बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने कार्य को पूरा कर सके।
- **पारदर्शति और जवाबदेही बढ़ाना:** गलतफहमियों को कम करने और आपसी वश्विवास बनाने के लिये RBI और सरकार दोनों द्वारा **नरिणय लेने में अधकि पारदर्शति** की आवश्यकता है। **वमिद्रीकरण (2016), PCA मानदंड, अधशेष हस्तांतरण असहमति** और मौद्रकि नीति मतभेद जैसे उदाहरण RBI-सरकार की प्राथमकिताओं को संरेखति करने और आपसी वश्विवास बनाने के लिये पारदर्शी नरिणय लेने की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- **स्पष्ट राजकोषीय-मौद्रकि नीति समन्वय:** सरकार को राजकोषीय वस्तितार की सीमाओं और मुद्रास्फीति नियंत्रण के संबंध में RBI की चर्चाओं को स्वीकार करते हुए **राजकोषीय और मौद्रकि नीतियों के बीच बेहतर समन्वय** का लक्ष्य रखना चाहति।
 - इसमें **नीति संरेखण के लिये औपचारकि तंत्र** शामिल हो सकता है, जसिसे यह सुनश्चिति हो सके कि दोनों संस्थाएँ एक समान आर्थकि लक्ष्य की दशिा में काम करें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. मौद्रकि नीति समति (MPC) के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है।
2. यह आरबीआई के गवर्नर सहति 12 सदस्यीय नकियाय है जसिका प्रतविरष पुनर्गठन किया जाता है।
3. यह केंद्रीय वतित मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक वस्तुवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन
2. सीमांत स्थायी सुवर्धा दर में बढ़ोतरी
3. बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/dispute-between-government-and-rbi>

